भारत-बेलारूस: नई दिल्ली में 12वाँ अंतर-सरकारी आयोग, व्यापार-निवेश को नई गति



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग (Inter-Governmental Commission, IGC) की 12वीं बैठक 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय पक्ष से वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और बेलारूस की ओर से विदेश मंत्री मैक्सिम रिझेंकोव ने इसकी सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्ष व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि और खनिज-क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। 13वाँ सत्र वर्ष 2027 में होगा।

परिचय: अंतर-सरकारी आयोग क्या है

अंतर-सरकारी आयोग (IGC): दो देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक-तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा व आगे बढ़ाने के लिए गठित नियमित मंत्री-स्तरीय तंत्र। यह अलग-अलग क्षेत्रों की कार्यकारी समितियों/कार्यदलों के माध्यम से प्रस्तावों को आगे बढ़ाता है और हर बैठक में संयुक्त दिशा तय होती है। भारत के कई देशों के साथ इसी तरह के आयोग हैं; बेलारूस के साथ यह तंत्र व्यापार-निवेश वार्ता का मुख्य मंच है।

मुख्य भाग: 12वीं बैठक के मुख्य निर्णय

- **व्यापार-विविधीकरण:** दोनों पक्षों ने पारंपरिक मदों से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार-पोर्टफोलियो में विविधता लाने पर जोर दिया।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि (फार्मास्युटिकल्स) और खनिज क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने की सहमति।
- **निवेश और तकनीक:** निवेश-अवसरों और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा; नियामकीय और मानकीकरण मुद्दों पर संवाद जारी रखने की बात।
- **अगला सत्र:** 13वाँ सत्र वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा (स्थल की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है)।
- **प्रतिनिधिमंडल:** बैठक में दोनों देशों के व्यापार-जगत और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।

परीक्षा के लिए महत्व

प्रिलिम्स की दृष्टि से: बैठक की संख्या (12वीं), स्थान (नई दिल्ली), तिथि (16 नवंबर 2026), सह-अध्यक्ष (जितिन प्रसाद - मैक्सिम रिझेंकोव) और सहयोग-क्षेत्र - प्रत्यक्ष प्रश्न-विषय।

मुख्य परीक्षा की दृष्टि से: छोटे देशों के साथ आर्थिक-कूटनीति, यूरेशिया में भारत की व्यापार-रणनीति, भू-राजनीतिक दबावों के बीच संबंध-संतुलन - GS-II विश्लेषण।

आगे की राह

बैठक में तय दिशा को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अब संबंधित मंत्रालयों और कार्यदलों पर है। वर्ष 2027 में होने वाले 13वें सत्र तक व्यापार-विविधीकरण और निवेश-परियोजनाओं में प्रगति देखी जाएगी।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न1. भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग की 12वीं बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: बैठक 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई
कथन 2: बेलारूस की ओर से विदेश मंत्री मैक्सिम रिझेंकोव ने सह-अध्यक्षता की
कथन 3: दोनों पक्ष 13वाँ सत्र वर्ष 2027 में आयोजित करने पर सहमत हुए

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: बैठक 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई; भारत की ओर से जितिन प्रसाद और बेलारूस की ओर से विदेश मंत्री मैक्सिम रिझेंकोव सह-अध्यक्ष थे; और 13वां सत्र 2027 में होने पर सहमति बनी।

प्रश्न2. भारत-बेलारूस 12वें IGC में सहयोग के लिए चिन्हित क्षेत्रों में कौन-सा शामिल नहीं है?

(a) कृषि

(b) खाद्य प्रसंस्करण

(c) अंतरिक्ष अन्वेषण

(d) औषधि

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c) अंतरिक्ष अन्वेषण

व्याख्या: बैठक में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि और खनिज क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने की सहमति बनी; अंतरिक्ष अन्वेषण इनमें शामिल नहीं है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

छोटे और मध्यम देशों के साथ अंतर-सरकारी आयोग जैसे तंत्र भारत की आर्थिक-कूटनीति में कैसे मदद करते हैं? भारत-बेलारूस संबंधों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: 12वें IGC और द्विपक्षीय व्यापार-निवेश को गहरा करने की सहमति का परिचय।

मुख्य भाग में: IGC की भूमिका - नियमित संवाद, क्षेत्रवार कार्यदल, नियामकीय मुद्दों का समाधान; खनिज (पोटाश आदि), फार्मा और कृषि-क्षेत्र की पूरकता; यूरेशिया में बाज़ार-विविधीकरण की रणनीतिक दृष्टि; चुनौतियां - भुगतान-तंत्र, रसद और प्रतिबंध-परिस्थितियां।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष रखें कि संस्थागत तंत्र दीर्घकालिक, स्थिर संबंध बनाते हैं; कार्यान्वयन पर ध्यान जरूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: भारत-बेलारूस IGC की 12वीं बैठक 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई, जिसमें व्यापार-निवेश गहरा करने, व्यापार में विविधता लाने और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि व खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी; अगला सत्र 2027 में होगा।

प्रश्न: बैठक की अध्यक्षता किसने की?

भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और बेलारूस की ओर से विदेश मंत्री मैक्सिम रिझेंकोव ने सह-अध्यक्षता की।

प्रश्न: IGC का काम क्या है?

यह दो देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा व आगे बढ़ाने वाला नियमित मंत्री-स्तरीय तंत्र है।

प्रश्न: अगली बैठक कब और कहाँ होगी?

13वाँ सत्र वर्ष 2027 में होगा; स्थल की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

स्रोत

- DD News - India, Belarus agree to deepen trade and investment ties at 12th Inter-Governmental Commission meeting: https://ddnews.gov.in/en/india-belarus-agree-to-deepen-trade-and-investment-ties-at-12th-inter-governmental-commission-meeting/

संबंधित लेख (आंतरिक लिंक)

- व्यापार की नई धार: भारत-थाईलैंड की 14वीं संयुक्त व्यापार समिति बैठक